भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 204

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

नौकरियों के अवसर बढ़ाने संबंधी योजनाएँ

204. श्री भोजराज नाग:
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री पी. सी. मोहन:
श्री बिद्युत बरन महतो:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री मनोज तिवारी:
श्री राजकुमार चाहर:
श्री गोडम नागेश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में 2014 से 2025 तक के दशक में सृजित सरकारी और निजी नौकरियों की संख्या का उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण बेरोजगारी दर में कोई कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत कुछ वर्षो में महिला रोजगार दर में कर्नाटक, विशेषकर बेंगलुरु सहित राज्यवार कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) क्या देश में रोजगार दर में वृद्धि हुई है और बेरोजगारी दर में कमी आई है और यदि हाँ, तो सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): युवाओं और महिलाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है।

तदनुसार, सरकार देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (डब्ल्यूआईएसई-किरण), एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन आदि कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार सृजन को समर्थन देने, सभी क्षेत्रों में नियोजनीयता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया गया है और 27 उद्योगों के रोजगार अनुमान प्रदान किए गए हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल अनुमानित रोजगार 2014-15 के दौरान 47.15 करोड़ की तुलना में 2023-24 के दौरान बढ़कर 64.33 करोड़ (अनंतिम) हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 36.44% की वृद्धि दर्शाता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 30.06.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 6.2 करोड़ से अधिक रिक्तियां (जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) जुटाई गई हैं।

रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोज़गारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। साथ ही, महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए यूआर 5.6% से घटकर 3.2% हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया है। साथ ही, महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक) के लिए डब्ल्यूपीआर 22.0% से बढ़कर 40.3% हो गया है। कर्नाटक राज्य में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक) के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित डब्ल्यूपीआर 2017-18 में 24.8% से बढ़कर 2023-24 में 37.2% हो गया है।

महिलाओं सहित बेरोजगारी (यूआर) और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा पीएलएफएस की रिपोर्टों में उपलब्ध है और इसे https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

*****